

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com



बीकानेर

Rashtradoot

फोन:- 2200660 फैंक्स : 0151-2527371

वर्ष: 47

संख्या: 187

प्रभात

बीकानेर, शुक्रवार 30 जनवरी, 2026

डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22

पृष्ठ 6

मूल्य 2.50 रु.

राजस्थान के वरिष्ठ नेतागण, खड़गे व राहुल गांधी से मिले दिल्ली में

मुलाकात का मुख्य ध्येय, ऐसा लगा है कि सचिन पायलट के खिलाफ वातावरण बनाना, जिससे डोटासरा अपने प्रदेशाध्यक्ष पद पर बने रहें व सचिन पायलट को प्रदेशाध्यक्ष बनने से रोका जा सके।

- रेणु मित्तल-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 जनवरी। राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ एक बैठक हुई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संदिग्ध रूप से अनुपस्थित रहे।

दिलचस्प बात यह है कि गहलोत एक महीने से अधिक समय से राजस्थान से गायब थे और लोगों द्वारा उनके ठिकाने को लेकर सवाल उठाए जाने के बावजूद, वे चुप्पी साधे हुए थे। हालांकि, दिल्ली में होने वाली बैठक से ठीक पहले आज सुबह अशोक गहलोत ने ट्वीट कर बताया कि डॉक्टरों ने उन्हें ठंडे स्थानों से दूर रहने और गर्म जलवायु में रहने की सलाह दी है, क्योंकि वे स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं।

बैठक के दौरान राहुल गांधी ने पूछा कि अशोक गहलोत कहाँ हैं, जिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने गहलोत को फोन मिलाया और फोन राहुल गांधी को दे दिया। राहुल ने उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा, और उन्हें बताया गया कि गहलोत को निमोनिया हुआ था और वे मुंबई के

- इस बैठक में अशोक गहलोत की अनुपस्थिति काफी चर्चित रही, हालांकि, बैठक से ठीक पहले गहलोत ने ट्वीट करके यह उजागर किया था कि वे मुम्बई में हैं तथा उन्हें निमोनिया हो गया था। अतः डॉक्टरों ने उन्हें हिदायत दी है कि ठंड से बचें और ऐसी गरम जगह पर रहें, जहाँ तापमान ज्यादा ठंडा न हो, बल्कि थोड़ा गरम हो।

- गहलोत ने यही बात राहुल गांधी को दोहराई, जब राहुल ने उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा, खड़गे द्वारा गहलोत को फोन मिलाने पर।

- भंवर जितेन्द्र सिंह, प्रभारी रंधावा, कांग्रेस के संगठन महासचिव वेणुगोपाल आदि की पूरी कोशिश है कि डोटासरा, प्रदेशाध्यक्ष बने रहें तथा सचिन पायलट को किसी भी तरह प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी से दूर ही रखा जा सके।

स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। गहलोत की बेटी मुंबई में रहती हैं और राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि गहलोत की अधिकांश संपत्ति मुंबई में ही है।

इस बैठक में सचिन पायलट के खिलाफ एक तरह से घेराबंदी भी देखने

को मिली, जहाँ वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा की जमकर तारीफ़ की, चाहे वह एसआईआर हो, बीएलए हो, मनरेगा हो या पार्टी संगठन व पार्टी को एकजुट रखने का मुद्दा हो।

डोटासरा और जूली की सराहना

करने वालों में भंवर जितेन्द्र सिंह, एआईसीसी प्रभारी रंधावा और संगठन मामलों के एआईसीसी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल प्रमुख रूप से शामिल थे।

सूत्रों के अनुसार, डोटासरा को मजबूत करने, उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पर बनाए रखने और किसी भी तरह से यह सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है कि सचिन पायलट डोटासरा की जगह न ले सकें।

भंवर जितेन्द्र सिंह की गांधी परिवार तक सीधी पहुँच मानी जाती है और वे लगातार 'गुपचुप कैम्पेन' चलाने के लिए जाने जाते हैं। रंधावा, डोटासरा के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, जिसके पीछे जाट समुदाय की बाँँटिंग को भी कारण बताया जा रहा है। वहीं, वेणुगोपाल भी काफी समय से डोटासरा की प्रशंसा करते आ रहे हैं, ताकि प्रदेश कांग्रेस की कमान उनके पसंदीदा व्यक्ति के हाथों में बनी रहे।

रंधावा ने आगामी राज्यसभा चुनावों का मुद्दा भी उठाया और कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नीरजा मोदी स्कूल सीधे हाई कोर्ट में याचिका नहीं लगा सकता- सीबीएसई

जयपुर, 29 जनवरी। कक्षा चार की बालिका अमाया की मौत के मामले में नीरजा मोदी स्कूल की समबद्धता वापस लेने के मामले में सीबीएसई ने हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश कर दिया है। हालांकि जवाब रिकॉर्ड पर नहीं आने के चलते, जस्टिस बिपिन गुप्ता की एकल पीठ ने नीरजा मोदी स्कूल की याचिका पर शुक्रवार के लिए सुनवाई टाल दी।

सीबीएसई की ओर से अधिवक्ता एमएस राघव ने कहा कि स्कूल प्रशासन को सीधे हाईकोर्ट में याचिका पेश करने का अधिकार नहीं है। इसके लिए, सीबीएसई चेयरमैन के समक्ष अपील पेश करनी चाहिए थी। घटना के बाद दो

- सीबीएसई के अधिवक्ता ने हाई कोर्ट में कहा कि स्कूल को पहले सीबीएसई चेयरमैन के समक्ष अपील पेश करनी चाहिए।

सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। जिसकी रिपोर्ट में स्कूल में कई तरह की गंभीर खामियां होने की बात सामने आई है, जैसे स्कूल के बच्चे आइडो कार्ड नहीं लगाते, जिससे घटना के आधा घंटा बाद तक यह पता नहीं चला कि चौथी मंजिल से कूदने वाली छात्रा कौन थी। इसके अलावा, इमारत पर सेफ्टी नैट भी नहीं था। इसके होने से घटना रोकी जा सकती थी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इकोनॉमिक सर्वे ने भी “डोमैस्टिक डिमांड” को ड्राइविंग इंजन माना

- अंजन राॅय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 29 जनवरी। केन्द्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी इकोनॉमिक सर्वे ने भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य के सम्बंध में “वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच स्थिर विकास” का नज़रिया पेश किया है, जिसमें “सावधानी बरतने, लेकिन निराशावादी न होने” की बात कही गई है।

इकोनॉमिक सर्वे (आर्थिक सर्वेक्षण) में वित्त वर्ष 2027 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.2 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें घरेलू कारकों की प्रमुख भूमिका बताई गई है।

सर्वेक्षण के अनुसार, वैश्विक माहौल अभी भी नाजुक बना हुआ है, हालांकि यह उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। इसके बावजूद भू-राजनीतिक तनाव, व्यापार में बंटवारा और वित्तीय कमजोरियाँ बढ़ रही हैं।

भारत के लिए राहत की बात यह है कि सर्वेक्षण मानता है कि वैश्विक हालात तत्काल बढ़े आर्थिक दबाव की बजाय, बाहरी अनिश्चितताएं पैदा कर सकते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार, “प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशों में धीमी वृद्धि, शुल्कों के कारण व्यापार में रुकावट और पूंजी प्रवाह में उतार-चढ़ाव समय-समय पर निर्यात और निवेशकों

- वित्त मंत्रालय द्वारा जारी “इकोनॉमिक सर्वे” के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ, विश्व की इकॉनमी में अनिश्चितता तो जरूर ला रही हैं, पर, देश की इकॉनमी पर इसका खास असर नहीं हुआ है।

- इसका मुख्य कारण है, देश की “डोमैस्टिक डिमांड” (आंतरिक खपत) के आंकड़े।

- सर्वे के अनुसार, देश की इकॉनमी के शानदार प्रदर्शन व महँगाई की दर पर नियंत्रण के कारण सरकार अब इस स्थिति में है कि नये-नये प्रोजैक्ट ला सके व महत्वाकांक्षी स्कीम्स ला सके।

- इससे, “डोमैस्टिक डिमांड” में उछाल आयेगा व नये रोज़गार की उपलब्धता बढ़ेगी।

की भावना पर असर डाल सकते हैं।”

घरेलू अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन पर आते हुए सर्वे ने कहा कि 2025-26 में घरेलू मांग ने आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ाया। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में अंतिम निजी उपभोग व्यय (पीएफसीई) की हिस्सेदारी बढ़कर 61.5 प्रतिशत हो गई।

सर्वे में इस बात पर जोर दिया गया है कि खपत में मजबूती एक अनुकूल व्यापक आर्थिक माहौल को दर्शाती है, जिसकी विशेषता, कम महँगाई, स्थिर रोजगार स्थिति और बढ़ती वास्तविक क्रय शक्ति है।

इसके अलावा, मजबूत कृषि प्रदर्शन से समर्थित स्थिर ग्रामीण खपत और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों के सरलीकरण से शहरी खपत में धीरे-धीरे सुधार के कारण उपभोग मांग की गति व्यापक आधार पर बनी रही। इसी संदर्भ में आर्थिक सर्वेक्षण में एक विरोधाभास नजर आता है।

आर्थिक सर्वेक्षण की प्रस्तावना में मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंतनारायणरवन ने कठोपनिषद का हवाला देते हुए कहा है कि भविष्य की तृप्ति के लिए वर्तमान उपभोग पर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

शशि थरूर, राहुल गांधी व खड़गे से मिलने गए

लम्बी मुलाकात में शिकवे-शिकायतें दूर हुईं तथा थरूर ने एक ही आग्रह किया, राहुल उन पर विश्वास करें

- रेणु मित्तल-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 जनवरी। लगातार सुर्खियों में रहे शशि थरूर की अंततः राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ एक लंबी और विस्तृत बैठक हुई, जिसमें कई गलतफहमियों को दूर किया गया। इस बैठक के बाद थरूर और राहुल गांधी के बीच एक कार्यकारी (वर्किंग) संबंध स्थापित हुआ।

यह बैठक केरल के कुछ सक्रिय कांग्रेस सांसदों की पहल का नतीजा थी, जिन्होंने के.सी. वेणुगोपाल से मुलाकात कर जोर दिया था कि राहुल गांधी और शशि थरूर को आपस में मिलकर अपने मतभेद सुलझाने चाहिए, अन्यथा कांग्रेस केरल खो सकती है।

एक वरिष्ठ पार्टी नेता ने कहा कि अधिकांश गलतफहमियाँ के.सी. वेणुगोपाल ने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के चलते पैदा की थीं। उनका कहना था कि यदि राहुल गांधी

- यह बैठक कांग्रेस के केरल से निर्वाचित सांसदों के जोर देने पर आयोजित की गई थी। इन सांसदों ने दबाव बनाया था कि राहुल गांधी व शशि थरूर अपने मतभेद साफ करके, नेतृत्व प्रदान करें राज्य में, अन्यथा कांग्रेस केरल में चुनाव हार जाएगी।

- शशि थरूर ने राहुल से यह भी कहा कि उन्होंने केरल में एक आमसभा को संबोधित करते हुए, थरूर का नाम भी नहीं लिया था, हालांकि वे मंच पर बैठे थे। राहुल ने जवाब दिया, उनको एक चिट दी गई थी, जिसमें वे नाम लिखे हुए थे, जिन्हें राहुल को संबोधित करना था, अपना भाषण शुरू करने से पहले। यह आम धारणा है, यह चिट में नाम न होना, वेणुगोपाल की शरारत थी।

- राहुल गांधी ने उसी समय यह भी आदेश दिए कि प्रदेशाध्यक्ष को पाबंद किया जाए कि हर पीसीसी बैठक में थरूर को लाज़मी तौर पर आमंत्रित किया जाए।

अब भी यह नहीं समझ पा रहे हैं कि वेणुगोपाल किस तरह अपनी

महत्वाकांक्षा, केरल का मुख्यमंत्री

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जद (एस) प्रमुख देवेगौड़ा प्रधानमंत्री से मिले

नयी दिल्ली 29 जनवरी। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने गुरुवार को यहाँ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं ने देश के विकास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर इस मुलाकात के बारे में

- देवेगौड़ा राज्यसभा सदस्य हैं तथा उनका दल राजग का हिस्सा है।

जानकारी दी।

मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा , " एच.डी. देवेगौड़ा जी के साथ उत्कृष्ट बैठक हुई। उनके महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार सराहनीय हैं। भारत के विकास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार सराहनीय हैं।

भारत के विकास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार सराहनीय हैं। भारत के विकास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार सराहनीय हैं।

भारत के विकास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार सराहनीय हैं। भारत के विकास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार सराहनीय हैं।

नफरती बयानबाजी कर भारी कानूनी विवाद में पड़ सकते हैं असम के मु.मंत्री

-श्रीनंदन झा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 जनवरी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा अपने बयानों को लेकर विवाद में फंसेते नजर आ रहे हैं। उन्होंने लोगों से “मियां मुस्लिम” रिक्शा चालकों को कम पैसे देने के लिए कहा था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार “मियां” समुदाय को “काबू में रखने” के लिए उन्हें परेशान करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि वे स्थानीय समुदाय पर हावी न हो सकें।

इससे पहले वे यह भी दावा कर चुके हैं कि विशेष पुनरीक्षण (स्पेशल रिवीजन) अभियान के दौरान पांच लाख मियां मुसलमानों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे।

सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति विभिन्न राज्यों, खासकर असम चुनाव प्रचार का लगातार हिस्सा रही है। असम में 1980 के शुरुआती वर्षों में “जनसंख्यिकीय घुसपैट” के खिलाफ बढ़ा जन आंदोलन हुआ था। वर्ष 2014 में असम की एक रेली में नरेन्द्र मोदी, जो तब भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, ने अवैध बांग्लादेशी

असम के मु.मंत्री हिमंत बिस्वा ने लोगों को मुस्लिमों को परेशान करने के लिए उकसाया

- मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक बयान में लोगों से अपील की कि मुसलमानों को परेशान किया जाए ताकि वे कमजोर हो जाएं। उन्होंने तरीका भी बताया, जैसे मुस्लिम रिक्शा वाले को कम किराया दिया जाए।
- ऐसी टिप्पणियाँ गैर जमानती, संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में आती हैं और अगर यह बयान संवैधानिक पद पर बैठे किसी नेता, जैसे मुख्यमंत्री, का हो तो बेहद गंभीर मामला बनता है।
- कांग्रेस की असम यूनिट ने इस संबंध में याचिका भी दायर की है।

प्रवासियों से कहा था कि वे अपना सामान बांधकर लौट जाएं। बारह साल बाद, केन्द्र और राज्य दोनों में भाजपा की सरकार होने के बावजूद यह समस्या अब भी बनी हुई है।

जब असम में नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (एन.आर.सी.) तैयार

किया गया, तब पाया गया कि 19 लाख अवैध प्रवासियों में से 11 लाख हिंदू थे। हैरानी की बात यह है कि भाजपा एनआरसी के इन निष्कर्षों को स्वीकार नहीं करती, लेकिन मौजूदा विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मियां समुदाय को निशाना बना रही है। इससे

विपक्षी भड़क गए हैं और आरोप लगा रहे हैं कि यह अल्पसंख्यकों को मताधिकार से वंचित करने के लिए किया जा रही एक लक्षित और सांप्रदायिक कवायव है।

सभी सरकारों को अवैध प्रवासियों को हटाने का अधिकार है। लेकिन यह अलग बात है कि कोई मौजूदा मुख्यमंत्री किसी खास समुदाय को सजा देने की खुली बात करे और उन्हें वोट देने के अधिकार से वंचित करने की धमकी दे। इस तरह की बातें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन हैं। साथ ही, यह बात भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए के तहत भी आ सकती है, जो धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास या भाषा के आधार पर अलग-अलग समूहों के बीच दुश्मनी, नफरत या वैमनस्य फैलाने को अपराध मानती है। यह अपराध संज्ञेय है, जमानत नहीं

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अजित पवार के विमान का ब्लैक बॉक्स मिला

नयी दिल्ली, 29 जनवरी। महाराष्ट्र के बारामती में बुधवार सुबह दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैकबॉक्स बरामद हो गया है।

जांच में शामिल अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि दुर्घटनाग्रस्त

- एएआईबी का जाँच दल बुधवार को बारामती में।

लीयरजेट 45 विमान का ब्लैकबॉक्स दुर्घटनास्थल से बरामद किया गया है। इस विमान हादसे में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उनके एक निजी सुरक्षा अधिकारी तथा एक सहायक और चालक दल के दो सदस्यों की मौत हो गयी थी। एएआईबी के महानिदेशक के नेतृत्व में जांच दल बुधवार को ही बारामती पहुँच गया था। इसके साथ नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के तीन अधिकारियों की मुंबई की टीम भी जांच कर रही है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

CMYK

● ● ● ●

⊕

● ● ● ●

⊕

● ● ● ●

⊕

● ● ● ●

CMYK

विचार बिन्दु

पुरुषार्थ से दरिद्रता का नाश होता है, जप से पाप दूर होता है, मौन से कलह की उत्पत्ति नहीं होती और सजगता से भय नहीं होता। –चाणक्य

परंपरा और तकनीकी मिलकर गढ़ रहे हैं नया राजस्थान

राजस्थान, जो कभी रेगिस्तानों और किलों की भूमि के नाम से जाना जाता था, आज परंपरा और तकनीकी के अनोखे संगम से एक नया स्वरूप धारण कर रहा है। यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत आधुनिक विज्ञान के साथ जुड़कर न केवल आर्थिक प्रगति को गति दे रही है, बल्कि युवा पीढ़ी को भी अपनी जड़ों से जोड़े हुए है।

यह संयोजन राजस्थान को वैश्विक पटल पर एक अनूठा राज्य बना रहा है, जहाँ ऊँटों के मेलों के साथ डिजिटल स्टार्टअप्स फल-फूल रहे हैं। परंपरागत हस्तशिल्प अब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिक रहे हैं, और प्राचीन लोकगीत डिजिटल संगीत ऐप्स में गूँज रहे हैं।

राजस्थान की परंपराएँ सदियों पुरानी हैं, जो लोककला, संगीत, नृत्य और वास्तुकला में झलकती हैं। यहाँ के त्योहार जैसे पुष्कर मेला या जैसलमेर का डेजर्ट फेस्टिवल रंग-बिरंगे परिधानों, कठपुतली नृत्य और भोपा गायकों से सजते हैं। महिलाएँ पनहारी गीत गाते हुए कुर्रें से पानी भरती हैं, जो उनकी दैनिक जीवन की कविता है। किले जैसे आमेर, मेहरानगढ़ और जैसलमेर का स्वर्ण किला पीले बलुआ पत्थरों से चमकते हैं, जो राजपूत शौर्य की गाथा कहते हैं।

इन परंपराओं में हस्तशिल्प का विशेष स्थान है। टाई-डाई, मिरर वर्क, ब्लॉक प्रिंटिंग और जरी कढ़ाई जैसी कला पीढ़ियों से चली आ रही है। बीकानेर की कठपुतलियाँ और जोधपुर की लकड़ी की नक्काशी पर्यटकों को लुभाती हैं। राजस्थानी व्यंजन जैसे दाल बाटी चूरमा कम पानी वाली जलवायु के अनुकूल हैं, जो स्थानीय कृषि पर आधारित हैं। ये परंपराएँ न केवल सांस्कृतिक पहचान हैं, बल्कि आजीविका का स्रोत भी। लेकिन बदलते समय में इन्हें तकनीकी से जोड़ना आवश्यक हो गया है।

तकनीकी क्रांति ने राजस्थान को तेजी से बदल दिया है। राज्य में सौर ऊर्जा संयंत्रों का जाल बिछा है, खासकर फलोदी और जैसलमेर जैसे क्षेत्रों में, जहाँ सूरज की प्रचुरता का लाभ उठाया जा रहा है।चंबल और माही नदियों पर बांधों से सिंचाई और बिजली मिल रही है, जो कृषि को आधुनिक बना रही है। जयपुर और जोधपुर में आईटी हब विकसित हो रहे हैं, जहाँ स्टार्टअप्स फल-फूल रहे हैं।

सौमेट उद्योग में राजस्थान देश में प्रथम है। लाखेरी और बूंदी के अलावा वर्तमान में सभी सीमेंट कारखाने अब उन्नत तकनीक से चलते हैं। कान्च उद्योग भी फलोदी, जयपुर और धौलपुर में पनप रहा है। डिजिटल इंडिया के तहत राजस्थान में ई-गवर्नेंस मजबूत हुआ है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएँ पहुँच रही हैं। मोबाइल ऐप्स से किसान फसल बेच रहे हैं, और ड्रोन से खेतों की निगरानी हो रही है।

यह संयोजन सबसे सुंदर रूप में पर्यटन में दिखता है। प्राचीन किले अब वर्चुअल रियलिटी से जुड़ गए हैं। जयपुर का हवा महल या आमेर किला पर्यटक ऐप्स पर 360 डिग्री दूर देते हैं। पुष्कर मेला लाइव स्ट्रीमिंग से वैश्विक दर्शकों तक पहुँच रहा है। जैसलमेर के घरों में परंपरागत डिवाइन के साथ सोलर पैनल लगे हैं, जो बीकानेर के एक घर का उदाहरण है जहाँ पुरानी वास्तुकला और आधुनिक तकनीक का संगम है।

हस्तशिल्प को तकनीकी ने नई उड़ान दी है। राजस्थानी ब्लॉक प्रिंट अब ऑनलाइन मार्केट्स

जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर बिकता है। डिजाइन सॉफ्टवेयर से आर्टिस्ट्स नए पैटर्न बना रहे हैं। जोधपुर की वुडन क्राफ्ट को 3डी प्रिंटिंग से मजबूती मिल रही है। ई-कॉमर्स ने स्थानीय कारीगरों को वैश्विक बाजार से जोड़ा है। उदाहरणस्वरूप, राजस्थानी साफा और जूतियाँ अब डिजिटल कैटलॉग्स में हैं, जो युवाओं को परंपरा से जोड़ते हैं।

कृषि क्षेत्र में यह मेल चमत्कारिक है। राजस्थान सूखा प्रभावित होने के बावजूद डिजिटल कृषि से बदल रहा है। किसान ऐप्स से मौसम पूर्वानुमान पाते हैं, और ड्रोन से बीज बोया जा रहा है। इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई बढ़ी है, जो परंपरागत खेती को आधुनिक बनाती है। जैसलमेर के रेगिस्तान में ड्रिप इरिगेशन से सब्जियाँ उग रही हैं। जैविक खेती को प्रमोट करने वाले ऐप्स किसानों को प्रीमियम दाम दिला रहे हैं। यह न केवल उत्पादन बढ़ा रहा है, बल्कि जल संरक्षण भी।

शिक्षा में भी परिवर्तन आया है। ग्रामीण स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम हैं, जहाँ बच्चे टेबलेट पर राजस्थानी लोककथाएँ सीख रहे हैं। जयपुर के विश्वविद्यालयों में एआई कोर्सेस राजस्थानी इतिहास पर आधारित हैं।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से युवा कठपुतली कला या लोकनृत्य सीख रहे हैं। यह परंपरा को जीवंत रखते हुए भविष्य की तैयारी करा रहा है। उदाहरण के लिए, भोपा गीतकार अब यूट्यूब पर अपनी प्रस्तुतियाँ अपलोड कर रहे हैं, जो लाखों व्यूज पा रहे हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीकी ने क्रांति ला दी। टेलीमेडिसिन से दूरदराज के गाँवों में डॉक्टर पहुँच रहे हैं। जोधपुर के एम्स में एआई से डायग्नोसिस हो रहा है। आयुर्वेद को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रमोट किया जा रहा है, जहाँ प्राचीन जड़ी-बूटियों आधुनिक रिसर्च से सिद्ध हो रही हैं। कोविड काल में राजस्थान ने डिजिटल हेल्थ ऐप्स से लाखों को बचाया।

सांस्कृतिक संरक्षण में डिजिटल अभिलेखागार महत्वपूर्ण हैं। राजस्थान सरकार ने विरासत को डिजिटाइज किया है। किलों की स्कैनिंग से 3डी मॉडल बने हैं, जो भूकंप जैसी आपदाओं से बचाव करेंगे। लोक संगीत को डिजिटल स्वरूप में संग्रहीत किया जा रहा है। एनजीओ और स्टार्टअप्स मिलकर राजस्थानी बोलियों को ऐप्स में ला रहे हैं। इससे युवा अपनी भाषा नहीं भूलेंगे।

आर्थिक प्रभाव गहरा है। तकनीकी ने रोजगार सृजित किए हैं। आईटी क्षेत्र में हजारों युवा कार्यरत हैं। ई-कॉमर्स से हस्तशिल्प निर्यात बढ़ा है। सौर ऊर्जा से ग्रामीण क्षेत्र आत्मनिर्भर बने हैं। स्टार्टअप इंडिया के तहत राजस्थानी उद्यमी उभर रहे हैं, जो परंपरागत उत्पादों को ब्रांड बना रहे हैं। उदाहरणस्वरूप, मोम्बतत मारजानी जैसी ब्रांड्स बेलेंस गाउन को ग्लोबल बना रही हैं। चुनौतियाँ भी हैं। डिजिटल डिवाइड ग्रामीण क्षेत्रों में है, जहाँ इंटरनेट कमजोर है। परंपराओं का व्यावसायिकीकरण उनकी शुद्धता को प्रभावित कर सकता है। युवा शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। लेकिन सरकार की योजनाएँ जैसे राज-ई-नित्र और डिजिटल गांव इनसे निपट रही हैं।

परंपरा और तकनीकी का यह संगम राजस्थान को सशक्त बना रहा है। यह न केवल आर्थिक विकास ला रहा है, बल्कि सांस्कृतिक निरंतरता भी सुनिश्चित कर रहा है। भविष्य में एआई और वर्चुअल दूरिज्म से राज्य चमकेगा। राजस्थान अब रेत के टीलों से आगे, डिजिटल रेगिस्तान का राजा बन चुका है।

यह प्रक्रिया समावेशी है। महिलाएँ ई-लर्निंग से सशक्त हो रही हैं। आदिवासी समुदाय डिजिटल मार्केटिंग से अपनी कला बेच रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण में स्मार्ट सेंसर रेगिस्तान को हरा बना रहे हैं। राजस्थान का यह नया स्वरूप प्रेरणादायक है।

वर्तमान समय में परंपरा तकनीकी को जोड़े है, और तकनीकी परंपरा के पंखा दोनों मिलकर राजस्थान को विश्व गुरु बना सकते हैं। युवाओं को इस संगम को अपनाना चाहिए। यह नया राजस्थान सिर्फ राज्य नहीं, एक विचार है जहाँ अतीत और भविष्य एक साथ चलते हैं।

–अविनाश जोशी,
अतिथि संपादक

वरिष्ठ पत्रकार एवं कॉरपोरेट सलाहकार

संपादकीय

राज्यपाल का अभिभाषण: विकसित राजस्थान की दिशा में सशक्त और सुनियोजित पहल

अभिभाषण में इस बात पर विशेष बल दिया है कि शासन की सफलता का वास्तविक पैमाना अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के जीवन में आने वाला सकारात्मक परिवर्तन है



डॉ. अरुण चतुर्वेदी

सोलहवीं राजस्थान विधानसभा के पंचम सत्र में राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण राज्य के विकास, सुशासन और जनकल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का सशक्त प्रतिबिंब है। यह अभिभाषण प्रदेश की वर्तमान उपलब्धियों, नीतिगत प्राथमिकताओं और भावी दृष्टि का समग्र, तथ्यपरक और परिणामोन्मुख दस्तावेज है। इसमें स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार सेवा, सुशासन और समावेशी विकास के मूल मंत्र को धरातल पर उतार रही है।

अभिभाषण में लोकतांत्रिक मूल्यों की गरिमा को रेखांकित करते हुए इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि

शासन की सफलता का वास्तविक पैमाना अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के जीवन में आने वाला सकारात्मक परिवर्तन है। इसी दृष्टि के अनुरूप राज्य सरकार ने विगत दो वर्षों में प्रशासनिक परदर्शिता, जवाबदेही और निर्णयों की गति को सुदृढ़ किया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए एसआईटी के माध्यम से सख्त कार्रवाई की गई। परिणामस्वरूप पिछले दो वर्षों में पेपर लीक की एक भी घटना सामने नहीं आई। भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं पर कठोर रुख अपनाने हुए 140 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज कर 420 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई, जिससे युवाओं के मन में विश्वास की पुनर्स्थापना हुई।

युवाओं के भविष्य को सुरक्षित और सशक्त बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रहा है। इसी संकल्प के साथ अब तक लगभग एक लाख युवाओं को सरकारी नियुक्तियाँ प्रदान की जा चुकी हैं, जबकि 1 लाख 54 हजार 547 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रगति पर है। वर्ष 2026 के लिए एक लाख सरकारी पदों का भर्ती कैलेंडर जारी किया जाना इस बात का प्रमाण है कि सरकार अवसरों को योजनाबद्ध ढंग से सृजित कर रही है।

खेलों के क्षेत्र में भी राजस्थान ने नई पहचान बनाई है। खेले इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स-2025 का सात शहरों में सफल आयोजन हुआ, जिसमें

देशभर के 222 विश्वविद्यालयों के लगभग 7 हजार खिलाड़ियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 49 खिलाड़ियों को 2 करोड़ 95 लाख रुपये की सहायता प्रदान कर राज्य ने प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया है।

शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने समान अवसर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को केंद्र में रखते हुए व्यापक सुधार किए हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 2 लाख 37 हजार से अधिक विद्यार्थियों को निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश दिलाया गया, जिसके लिए लगभग 996 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की गई। वहीं, सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत 66 लाख से अधिक विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म एवं स्कूल बैग उपलब्ध कराने हेतु 482 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई।

विगत दो वर्षों में 185 नए महाविद्यालय भवनों का लोकार्पण, 71 नए महाविद्यालयों की स्थापना और 17 महाविद्यालयों का स्नातकोत्तर स्तर पर उन्नयन किया जाना राज्य की उच्च शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तकनीकी शिक्षा को भविष्य की आवश्यकताओं से जोड़ते हुए 21 नए पॉलिटेक्निक महाविद्यालय प्रारंभ किए गए तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग नीति लागू कर राजस्थान को तकनीकी नवाचार के अग्रणी राज्यों

की श्रेणी में स्थापित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं।

कृषि एवं किसान कल्याण को राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानते हुए सरकार ने वित्तीय, संरचनात्मक और तकनीकी सहयोग को प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 71 लाख 79 हजार किसानों को लगभग 718 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। समर्थन मूल्य पर 21 लाख 37 हजार मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद कर किसानों को 320 करोड़ रुपये का बोनस दिया गया। इसके साथ ही, अल्पकालीन व्याज मुक्त फसली ऋण के रूप में 78 लाख से अधिक लाभार्थियों को 44 हजार 355 करोड़ रुपये वितरित किए गए, जिससे किसानों की तात्कालिक जरूरतों की पूर्ति के साथ उनकी आय में स्थायित्व आया है।

महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी राज्य सरकार की पहलें प्रभावी सिद्ध हो रही हैं। 15 लाख 95 हजार महिलाओं को 'लक्षपति दीदी' श्रेणी में लाकर उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाया गया है। सामाजिक सुरक्षा पंशन योजनाओं के अंतर्गत 91 लाख 73 हजार लाभार्थियों को 12 हजार 700 करोड़ रुपये का भुगतान सुनिश्चित किया गया। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 103 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए

हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना राज्य की पहचान बनकर उभरी है। इसके अंतर्गत 1 करोड़ 36 लाख परिवारों को 25 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। विगत दो वर्षों में लगभग 37 लाख रोगियों को 7 हजार 300 करोड़ रुपये से अधिक का निःशुल्क उपचार प्रदान किया गया। राजस्थान ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है। फरवरी 2025 में 19 हजार 165 मेगावाट की अधिकतम बिजली मांग बिना कटौती के पूरी की गई, वहीं किसानों को 46 हजार 500 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाया गया है।

समग्र रूप से अभिभाषण इस तथ्य को रेखांकित करता है कि राजस्थान सरकार ने विकास को ठोस क्रियान्वयन, मापनीय परिणामों और जन विश्वास से जोड़ा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश विकसित भारत-विकसित राजस्थान के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। सुशासन, समावेशी विकास और दीर्घकालिक ओदृष्टि के साथ राजस्थान आज एक सशक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध भविष्य की ठोस आधारशिला बल चुका है।

–डॉ. अरुण चतुर्वेदी,
अध्यक्ष, राजस्थान वित्त आयोग

ऐसे तो “विकसित भारत” नहीं बनेगा

विकसित भारत यदि केवल बातों और नारों से हो जाता तो शायद भारत कभी का विकसित हो चुका होता



राजेन्द्र भाणावत

जब से प्रधानमंत्री मोदी ने

2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और 'विकसित भारत' बनाने की बात कही है, सत्ता धारी दल के सभी नेताओं के भाषणों एवं सरकार की सभी योजनाओं में 'विकसित भारत' शब्द सम्मिलित हो गया है। इसका सबसे ताजा उदाहरण तो हाल ही में घोषित "विकसित भारत-जी राम पी" योजना है, जिसे नरेंगा के स्थान पर लाया गया है।

विकसित भारत यदि केवल बातों और नारों से हो जाता तो शायद भारत कभी का विकसित हो चुका होता। इसी प्रकार का एक नारा 'गरीबी हटाओ' तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था, किंतु गरीबी आज भी ज्यों की त्यों है तथा गरीब और अमीर के बीच खाई तो पहले से भी कहीं अधिक चौड़ी हो गई है।

सरकार के प्रयास भी भारत को विकसित बनाने की ओर दिखाई नहीं देते। यदि यही स्थिति रही तो यह सपना केवल सपना ही बनकर रह जाएगा और कभी साकार होकर धरातल पर नहीं उठेगा। हम वर्तमान में किस प्रकार की प्राथमिकताएँ तय कर रहे हैं और किस प्रकार की दिशा में जा रहे हैं, उसके लिए कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना उपयुक्त होगा।

इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ शहर कई बार घोषित किया जा चुका है। इसी इंदौर शहर में सीवर का दूषित पानी पीने से 27 लोगों की मौत हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र के निवासी लगभग आठ महीने से स्थानीय प्रशासन और जन प्रतिनिधियों को गंदा पानी आने की शिकायत कर रहे थे किंतु किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। परिणामस्वरूप

इसी मलमूत्र युक्त पानी को नागरिक पीते रहे और सैकड़ों की संख्या में लोग बीमार हो कर अस्पतालों के आई सी यू में पहुँच गए। जब मामला मीडिया में बहुत चर्चित हुआ तब जाकर प्रशासन की आँख खुली और इस दिशा में कुछ कार्रवाई की गई। जो शहर लगभग देश में सबसे स्वच्छ शहर का इनाम प्राप्त कर रहा हो, वहाँ के मासूम नागरिकों को यदि गंदा पानी पीने के कारण काल कबलित होना पड़े तो यह विकसित भारत की दिशा में बढ़ता कदम तो कतई नहीं कहा जा सकता।

उत्तर प्रदेश के नोएडा में हाल ही में एक कार ऐसे खड़े में गिर गई जहाँ 35 फीट पानी भर हुआ था। यह खड्डा किसी भवन के बेसमेंट के निर्माण के लिए बनाया गया था और लगभग दो वर्षों से इस स्थिति में था। कोहरे के कारण दिखाई कम दे रहा था और कार चालक इस पानी में चला गया। यह 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता था जिसने हिममत रखकर डूबने से पहले कार के ऊपर खड़े होकर दो घंटे तक मोबाइल की रोशनी से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। उसने अपने पिता को अपनी लोकेशन भेज दी जिन्होंने फोन नंबर 112 पर सूचित भी कर दिया। जिला प्रशासन, पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस आरएफ के सैकड़ों लोगों के आने के बावजूद किसी ने उसे बचाने का प्रयास तक नहीं किया और मृक दर्शक बने रहे।

इसका कोई उत्तर प्रशासन के पास नहीं है कि केवल 15-20 किलोमीटर दूर हिंडन एयर बेस पर उपलब्ध हेलीकॉप्टर की मदद से उस युवक को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? जब किसी डूबते हुए युवक को आधुनिकतम तकनीक के सहारे सुशासन देने का दावा करने वाली उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2 घंटे तक नहीं बचाया जा सकता, तो विकसित भारत की बात करना बेमानी होगा। यही वह राज्य है जहाँ नोएडा के पास जेवर में विश्व स्तरीय हवाई अड्डा बनने की बात हो रही है। सरकार ने शायद यह समझ लिया है कि विश्वस्तरीय एयरपोर्ट बनाने, बुलेट ट्रेन चलाने से आधुनिकतम भवन

बनाने से, महंगी गाड़ियों में चलने से या बड़े-बड़े स्टेडियम बना देने से भारत विकसित हो जाएगा। सरकार को यह समझना होगा कि भारत विकसित तब होगा जब लोगों की शुद्ध वायु और पेयजल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा और योग्यता अनुसार रोजगार उपलब्ध हो।

जहाँ तक वायु प्रदूषण का सवाल है, स्थिति इतनी खराब है कि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी नेसल स्टिप लगाकर बाहर निकल रहे हैं, ताकि कहीं बीमार ना पड़ जाएँ। जिस देश की राजधानी का ए क्यू आई 800 तक हो जाए, वह देश कैसे विकसित कहला सकता है। निवेश लाने के लिए सरकार बड़े-बड़े दावे कर रही है और निवेशकों को लुभाने के लिए करोड़ों, अरबों रुपए खर्च भी करती है, किंतु यह भूल जाती है की मूलभूत सुविधाओं के अभाव में कोई भी विदेशी निवेशक यहाँ आकर निवेश करना उचित नहीं समझेगा। बाहर के लोग जब आकर आकर सांस तक न ले पाएँ, पीने का साफ पानी तक ठीक से न मिल पाए, तो वहाँ आयेगी ही क्यों?

भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ, जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उप प्रबंध निदेशक रह चुकी हैं और वर्तमान में हार्वर्ड में प्रोफेसर हैं, ने दावोस में आयोजित होने वाले वर्ल्ड इकनोमिक फोरम में बातचीत करते हुए यह स्पष्ट रूप से कहा कि भारत में निवेश तब ही आएगा जब भारत सरकार प्रदूषण की गंभीर स्थिति के संबंध में प्रभावी कार्रवाई करे।

गीता गोपीनाथ ने हॉर्नब्यु टुडे ग्रुप की मालकिन कली पूरी से यह बात कही जब उनसे भारत में अच्छे होते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संबंध में पूछा गया। उन्होंने कहा कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 1.8 लाख लोग केवल प्रदूषण के कारण परते हैं। यह स्वीकार्य नहीं है। उनके अनुसार "इज ऑफ डूइंग बिजनेस" का कोई अर्थ नहीं है यदि देश में शुद्ध वायु तक उपलब्ध नहीं है। आप कितने ही लाल कालीन विदेशियों के लिए भारत आने पर क्यों न बिछा दें, हवा में इतनी गंदगी है कि कोई भी व्यक्ति भारत आने से पहले 10 बार सोचेगा। जो बातें भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ

ने कही हैं उनको सरकार को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए और उन पर रक्षायक रूप अपनाने के बजाय उस दिशा में कार्रवाई करनी चाहिए। समय आ गया है जब नेता गुणों की केवल अपने और अपने परिवार की सुख सुविधा पर ध्यान देने की बजाय उन्हें साधारण जनता की सुविधा को बेहतर करने और उनके जीवन को सरल बनाने की दिशा में प्रयास करने होंगे। यदि यहाँ के जन प्रतिनिधि और अधिकारी गुण स्वयं को जनता का मालिक मानते रहे तो कभी भी देश न तो आत्मनिर्भर हो पाएगा और ना ही वह विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर हो पाएगा। अतः यदि भारत विकसित होना है कि देश में प्रगति हो, औद्योगीकरण बढ़े और बाहर से निवेश आए तो उसे पहले वायु और जल प्रदूषण को नियंत्रित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। भारतीयता की एक प्रख्यात प्रोफेसर का दावोस में विदेशी समुदाय के समक्ष इस प्रकार की बात करना भारत सरकार को आईना दिखाने के समान है।

नगरीय प्रशासन व्यवस्था लगभग ठप्प है। महानगरों में रहने वाली आबादी का लगभग 40 प्रतिशत नगरीय जीवन जी रहा है। दिल्ली में संसद भवन से केवल 40-50 किलोमीटर दूर किराड़ी जैसी अनेक बस्तियाँ हैं जहाँ लोगों को प्रतिदिन एक फुट सीवर के पानी के बीचवृद्ध में पाँव रखकर अपने घरों में जाना पड़ता है। इस क्षेत्र के वीडियो सोशल मीडिया में प्रतिदिन देखने को मिलते हैं जिन्हें देखकर स्वयं को भारतीय कहने पर शर्म आने लगती है। विकसित होने की बात करने से पहले हमें यहाँ के नागरिकों को कम से कम मनुष्य के लिए जीने लायक व्यवस्था तो उपलब्ध करानी होगी।

सरकार भले ही सोमनाथ में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ मनाने में लोगों को लगा दे, किंतु इससे लोगों का जीवन बेहतर नहीं होगा। आप किसी भी शहर में चले जाएँ, कूड़े के ढेर, गंदे पानी से अटी सड़कें, जर्जर स्कूल और बिना चिकित्सक के अस्पताल मिल जाएंगे। रोजगार का हाल यह है कि स्नातक और तकनीकी शिक्षा प्राप्त लोग भी

डिलीवरी बाँयज़ की तरह काम करने के लिए मजबूर हैं।

विकसित भारत का नमूना हाल ही में हमें देखने को मिला जब प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात के प्रमुख शहर सूरत में 21 करोड़ की लागत से बनी नई पानी की टंकी, जिसकी क्षमता 11 लाख लीटर की थी, 9 लाख लीटर के पानी का वजन भी नहीं सह सकी और पहली बार में ही ढह कर जमीन पर गिर गई। क्या इस पर व्यय हुए 21 करोड़ किसी अधिकारी से वसूल होंगे?

विकसित भारत तभी बनेगा जब लोगों को धर्म, जाति के प्रपंचों में उलझाए रखने और उन्हें तथाकथित इतिहास की गौरव गाथा का गुणगान करने में व्यस्त रखने के बजाय उनकी वर्तमान ज्वलंत समस्याओं की ओर ध्यान दिया जाए। शिक्षित और वैज्ञानिक सोच वाले समाज के अभाव में विकसित भारत की कल्पना करना संभव नहीं है। सरकार ने विकास का अर्थ उत्कृष्टता के टापू बनाना ही मान लिया है। यह विकसित भारत की दिशा में बढ़ता हुआ कदम नहीं कहा जा सकता।

जहाँ शहरों के फुटपाथ अनुपयोगी वाहनों से भरे पड़े हों, सड़कों पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करना जैसे लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार हो, वह भारत विकसित कैसे बनेगा? जहाँ अंधविश्वास, लोगों को कदम कदम पर परोसा जाता हो, बाबाओं को 'जेड' श्रेणी की सुरक्षा दी जाती हो और आम जनता को वाहनों के नीचे कुचले जाने के लिए छोड़ दिया जाता हो, उसे हम विकसित भारत कैसे कहेंगे?

अशिक्षित, बीमार, बेरोजगार और असुरक्षित नागरिकों के भारत को कभी भी विकसित भारत नहीं कहा जाएगा, न ही उस भारत को विकसित कहा जाएगा, जहाँ शुद्ध पेयजल उपलब्ध न हो, शहरों में गंदगी के ढेर लगे हों और जहाँ कानून का राज नहीं हो। विकसित भारत बनाने के लिए सरकार को अपनी प्राथमिकताओं का उपरोक्तानुसार पुनर्निर्धारण करना होगा ताकि सही दिशा में तेजी से अग्रसर हो सके।

–राजेन्द्र भाणावत, (पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)



पंडित अनिल शर्मा

मिथुन, मंगल-मकर, बुध-मकर, गुरु-मिथुन, शुक्र-मकर, शनि-कुम्भ, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह
आज सर्वाथि सिद्धि योग रात्रि 3:27 से सूर्योदय तक है। रवियोग रात्रि 3:27 से आरम्भ होगा। आज प्रदोष व्रत, वैधुति पुण्य, कल्पादि है।
श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:38 तक, लाभ-अमृत 8:38 से 11:19 तक, शुभ 12:40 से 2:01 तक, चर 4:42 से सूर्यास्त तक।
राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 7:18, सूर्यास्त 6:03

राशिफल

शुक्रवार 30 जनवरी, 2026

माघ मास, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत् 2082, आर्द्रा नक्षत्र रात्रि 3:27 तक, वैधुति योग रात्रि 4:58 तक, बालव कर्ण दिन 11:10 तक, चन्द्रमा आज मिथुन राशि में संचार करेगा।
गृह स्थिति: सूर्य-मकर, चन्द्रमा-मिथुन, मंगल-मकर, बुध-मकर, गुरु-मिथुन, शुक्र-मकर, शनि-कुम्भ, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

3:27 से आरम्भ होगा। आज प्रदोष व्रत, वैधुति पुण्य, कल्पादि है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:38 तक, लाभ-अमृत 8:38 से 11:19 तक, शुभ 12:40 से 2:01 तक, चर 4:42 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 7:18, सूर्यास्त 6:03



मेघ

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। व्यक्तिगत प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। प्रतिष्ठित व्यक्ति से संपर्क बन सकता है। व्यावसायिक सफलता से मनोबल बढ़ेगा।



तुला

व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटक के हुए कार्य बचने लगेगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा।



वृष

आर्थिक कारणों से अटक हुए कार्य बनने लगेगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। चलते कार्यों में प्रगति होगी।



वृश्चिक

अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब होने का भय है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। यात्रा में परेशानी हो सकती है।



मिथुन

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटक हुए कार्य बनने लगेगे। व्यावसायिक अडचन दूर होने लगेगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



धनु

परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। अपसी सहयोग-समन्वय से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

